

# ऑफर!!!ऑफर!!!ऑफर!!!

जयपुर मे किसी भी विवादित जमीन या सरकारी जमीन का किरायानामा दिखाओ  
और पूरे साल आबकारी विभाग से शराब बेचने का लाईसेंस पाओ!!



आबकारी विभाग, जयपुर शहर द्वारा  
भूखंड संख्या बी-213 लक्ष्मी नारायणपुरी, दिल्ली बाईपास पर  
लाईसेंस प्रतीक चौधरी को स्वीकृत की गई कम्पोजिट शराब की दुकान का मामला!!  
आवासीय भूखंड संख्या बी-213, लक्ष्मीनारायणपुरी के मालिकाना हक को लेकर  
दो विवाद चल रहे स्थानीय न्यायालयों में!!  
न्यायालयों में प्रस्तुत वादों के अनुसार जमीन पर तीन पार्टियां जता रही अपना हक!!  
मौके पर यथास्थिति के आदेश!!लेकिन इसके बावजूद स्टेशुदा जमीन पर  
एक पार्टी विशेष के कब्जे पर मोहर लगाते हुए, स्वीकृत कर दी गई शराब की दुकान!!

दुकान स्वीकृत करने से पहले ही पूरा मामला  
स्थानीय आबकारी निरीक्षक से लेकर जिला आबकारी अधिकारी के संज्ञान में!!  
लेकिन इसके बावजूद राजस्व हित की आड़ लेकर  
स्वीकृत की गई विवादित भूखंड पर शराब की दुकान!

एक शराब ठेकेदार विशेष पर  
जिला आबकारी विभाग की विशेष कृपा के चलते, खेला गया यह खेल!!  
मुख्यमंत्री के आदेशों की खुद आबकारी विभाग ही उड़ा रहा धजियां!!  
खुद मुख्यमंत्री महोदय विवादित जमीनो और भूमाफियाओ  
के खिलाफ कार्यवाही करने के प्रति गंभीर!!

लेकिन इसके बावजूद हर साल दर्जनों विवादित जमीनो पर  
आबकारी विभाग राजस्व का वास्ता देकर लगा रहा शराब की दुकाने!!

मुख्यमंत्री के आदेशों की आबकारी विभाग ही उड़ा रहा धजियां!!खुद मुख्यमंत्री महोदय विवादित जमीनो और भूमाफियाओ के खिलाफ कार्यवाही करने के प्रति गंभीर!!लेकिन इसके बावजूद हर साल सैंकड़ों विवादित जमीनो पर आबकारी विभाग राजस्व का वास्ता देकर लगा रहा शराब की दुकाने!!

गत वर्ष दिसंबर माह मे पुलिस

मुख्यालय मे हुई अपराध समीक्षा बैठक मे मुख्यमंत्री द्वारा रात 8 बजे शराब बंद करने के आदेश के बावजूद कई जगह इनके खुले रहने पर चिंता जताई गई थी।इसी के साथ राज्य मे जमीनो पर कब्जा करने,फर्जी पट्टे,एक प्लॉट के कई पट्टे जारी करने आदि मामलों और विवादित/सरकारी जमीनो पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओ के बढ़ते प्रभावों पर अंकुश लगाने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता मे कमिटी बनाने का एलान किया था।ऐसे मामलों पर चिंता जताते हुए उनके द्वारा बताया गया था कि जयपुर विवादित मामलों मे सिरमोर है,उनके अनुसार जयपुर मे ही जमीन विवादों से संबंधित 50 हजार

शिकायते लंबित है।इसी के साथ उनके द्वारा अपराधियों से

साँठ-गांठ करने वाले सरकारी अधिकारियों को भी आगाह करते हुए बताया गया था कि ऐसे मामलों मे सरकारी अधिकारियों की लिप्तता पाए जाने पर उन्हें तुरंत गिरफ्तार या बर्खास्त किया जाएगा।

लेकिन लगता है मुख्यमंत्री के इन आदेशों की आबकारी विभाग के अधिकारियों को कोई परवाह नहीं है तभी तो हर साल राज्य मे लाईसेंसशुदा शराब की दुकानों की लोकेशनस् स्वीकृत करने के नाम पर आवासीय,कृषि जमीनो पर कई अवैध दुकाने खोल दी जाती है।इतना ही नहीं सैंकड़ों मामलों मे स्थानीय भूमाफियाओ द्वारा विवादित और सरकारी जमीनो पर भी कब्जे कर,आबकारी विभाग से शराब की दुकान चलाने का लाईसेंस हासिल करने का खेल खेला जा रहा है।

माफियाओं की जांच के लिए गृह सचिव के नेतृत्व में गठित होगी



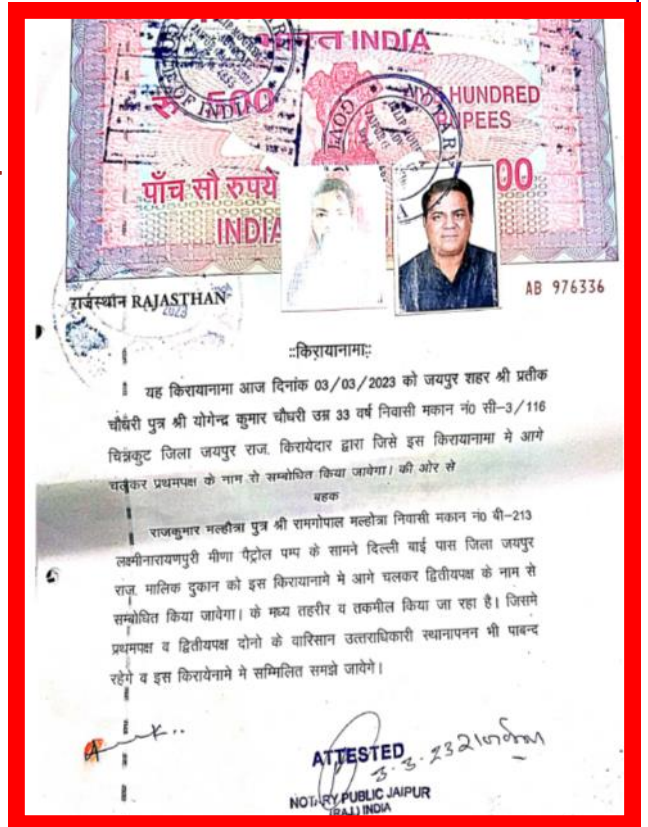
## कैसे खेला जाता है विवादित और सरकारी जमीनो पर शराब की दुकान का लाईसेंस लेने का खेल?

आपको बता दें कि किसी भी जिले में शराब की दुकान की लोकेशन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संबंधित आबकारी निरीक्षक की अनुशंसा पर स्वीकृत की जाती है। एक ईमानदार आबकारी निरीक्षक द्वारा नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें किसी शराब की दुकान की लोकेशन की अनुशंसा करने के समय, दस्तावेजों के नाम पर मात्र लाईसेंस के हक में निष्पादित किरायेनामे की दरकार होती है, और मौके पर दुकान का कब्जा मकान मालिक/लाईसेंस के पास होना चाहिए। इसके बाद भले ही वह जमीन आवासीय, कृषि हो या फिर विवादित अथवा सरकारी; आबकारी विभाग को इससे फर्क नहीं पड़ता।

इस पूरे खेल में संबंधित दुकान मालिक या शराब ठेकेदार द्वारा स्थानीय आबकारी निरीक्षक से लेकर जिले में बैठे आला अधिकारियों की जेबें गरम की जाती हैं। कई मामलों में यदि कोई विरोध आता है तो अपने आला अधिकारियों को राजस्व हित का वास्ता देकर राजी कर लिया जाता है। इस खेल में जहां एक और शराब ठेकेदार पूरे साल चांदी कुटता नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ उक्त विवादित या सरकारी जमीन पर सरकारी ठेका चलाने का ठप्पा लग जाता है, जिससे उस जमीन से संबंधित सभी विवादों पर विराम लग जाता है।

## क्या है आबकारी विभाग, जयपुर शहर द्वारा विवादित भूखंड संख्या बी-213 लक्ष्मी नारायणपुरी, दिल्ली बाईपास पर लाईसेंस प्रतीक चौधरी को स्वीकृत की गई कम्पोजिट शराब की दुकान का मामला!!

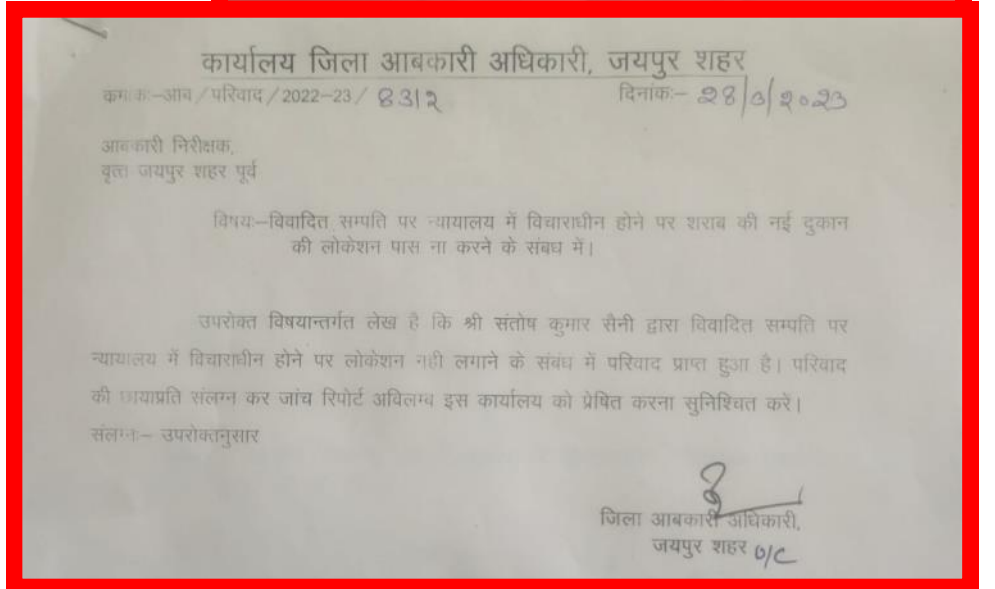
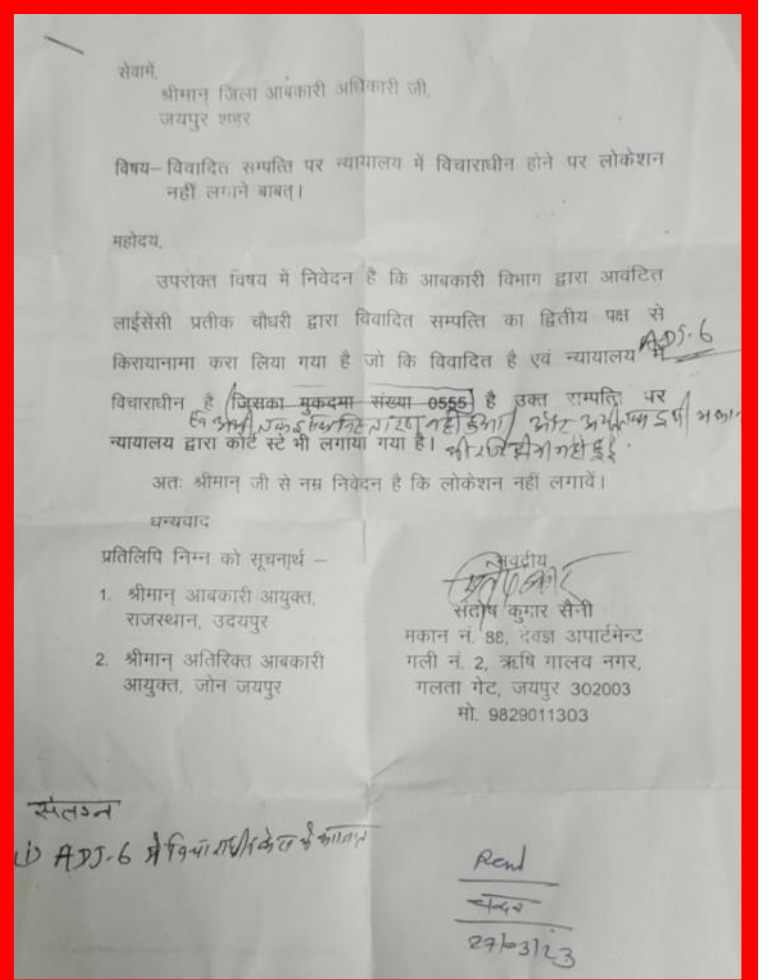
आपको बता दें कि आबकारी जयपुर शहर पूर्व में स्थित वार्ड संख्या 29,30,61,62,66,77 में स्थित लाईसेंस प्रतीक चौधरी द्वारा भूखंड संख्या बी-213 लक्ष्मीनारायणपुरी स्थित दो दुकानों पर दिनांक 05/04/2023 से शराब की कम्पोजिट दुकान संचालित की जा रही है। तुषार चौधरी द्वारा इस दुकान की लोकेशन स्वीकृत करवाने हेतु दिनांक 03/03/2023 को निष्पादित एक किरायानामा, जिसमें उक्त भूखंड बी-213 लक्ष्मीनारायणपुरी का मालिक राजकुमार मल्होत्रा का होना बताया गया, प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर संबंधित आबकारी निरीक्षक की अनुशंसा पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा इस दुकान को दिनांक 05/04/2023 को स्वीकृत की गई थी। यहाँ तक तो आपको सब ठीक लग रहा होगा, लेकिन इस मामले का दूसरा पहलू कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है।



इस भूखंड बी-213 लक्ष्मीनारायणपुरी पर शराब की दुकान लगने की खबर से कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। दिनांक 27/03/2023 को संतोष कुमार सैनी निवासी गलता गेट द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि लाईसेंस प्रतीक चौधरी द्वारा जिस संपत्ति का द्वितीय पक्ष से किरायानामा बताया गया है, वह विवादित है और न्यायालय में विचाराधीन है। इसी के साथ उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बताया गया कि उक्त संपत्ति पर न्यायालय द्वारा स्टे लगाया हुआ है और जिस संपत्ति को द्वितीय पक्ष अपना बता रहा है उस मकान की अभी तक रजिस्ट्री भी नहीं हुई है। अपने प्रार्थना पत्र के साथ परिवारी द्वारा ADJ-6 में विचाराधीन केस के दस्तावेज भी संलग्न किए जाते हैं।

संतोष कुमार सैनी के इस प्रार्थना पत्र पर जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर द्वारा दिनांक 28/03/2023 को इस प्रकरण की जांच हेतु उसी आबकारी निरीक्षक (वृत्त जयपुर शहर पूर्व) को भेज दी जाती है, जिसके द्वारा इस विवादित भूखंड पर शराब की दुकान लगाने की अनुशंसा की जानी थी। जब बिल्ली को ही छींके की रखवाली सौंप दी जाती है तो जो हाल छींके का होता है, वही हाल इस प्रकरण में भी हुआ, सूत्रों के अनुसार

संबंधित आबकारी निरीक्षक द्वारा इस प्रकरण में अपने आला अधिकारी को जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा और मामले को ठंडे बस्ते में डाल कर दिनांक 05/04/2023 को इसी आबकारी निरीक्षक की अनुशंसा पर इन्हीं जिला आबकारी अधिकारी महोदय द्वारा प्रतीक चौधरी को लाईसेंस हेतु शराब की दुकान की लोकेशन स्वीकृत कर दी गई।



आबकारी अधिकारियों की मनमानी के चलते दिनांक 13/04/2023 को पुनः संतोष कुमार सैनी द्वारा आबकारी आयुक्त, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर को लिखित में पुनः शिकायत देकर बताया गया कि जिस संपत्ति को राजकुमार मल्होत्रा द्वारा अपना बताया जा रहा है वह उसके नाम नहीं होकर

परिवादी संतोष सैनी के नाम है, अपने पक्ष की पुष्टि करने हेतु उनके द्वारा एक रजिस्ट्री की प्रति भी लगाई गई जिसमें उक्त भूखंड का स्वामित्व परिवादी संतोष कुमार सैनी के नाम होना बताया गया। लेकिन पूरा मामला कांच की तरह साफ होने के बावजूद जिम्मेदार आबकारी अधिकारी “ जिसकी लाठी उसकी भैंस” मुहावरे को चरितार्थ करते हुए, कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

### आवासीय भूखंड संख्या बी-

**213, लक्ष्मीनारायणपुरी के मालिकाना हक को लेकर दो विवाद चल रहे स्थानीय न्यायालयों में!!**  
**न्यायालयों में प्रस्तुत वादों के अनुसार विवादित जमीन पर तीन पार्टियां जता रही अपना हक!!**

इस पूरे प्रकरण में तीन पार्टियां सामने आ रही हैं जो इस विवादित जमीन पर अपना-अपना हक जता रही हैं और इन तीनों पार्टियों में इस विवादित जमीन को लेकर दो वाद स्थानीय न्यायालयों में लंबित हैं। पहले मामले में सतीश गुप्ता और सत्यनारायण गुप्ता द्वारा संतोष कुमार सैनी के विरुद्ध ADJ-3 में वाद दायर कर रखा है अपने वाद में गुप्ता बंधुओं उनके द्वारा बताया गया है, उनके द्वारा वर्ष 2016 में ही उक्त भूखंड की रजिस्ट्री संतोष कुमार सैनी के नाम करवा दी थी। लेकिन तय रजिस्ट्री के अनुसार संतोष कुमार द्वारा रजिस्ट्री में वर्णित चैकों का भुगतान नहीं किया गया है, वही इस मामले में संतोष कुमार की दलीलों के अनुसार उनके द्वारा पूरे पैसों का भुगतान कर दिया गया है, गुप्ता बंधुओं की नियत में खोट के चलते झूठा वाद दाखिल किया गया है। इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए न्यायालय द्वारा संतोष कुमार सैनी के पक्ष में यथास्थिति के आदेश जारी किए गए हैं।

**भूखंड संख्या बी-213 में मकान को तोड़कर बनाई गई दुकानें, जिन्हें तोड़ने का प्रकरण संबंधित जोन में लंबित है।**



दूसरे मामला संतोष कुमार सैनी और राजकुमार मल्होत्रा के मध्य ADJ-6 में लंबित है जिसमें संतोष कुमार सैनी द्वारा बताया गया है कि राजकुमार मल्होत्रा द्वारा दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित इकरारनामे दिनांक 06/06/2021 के अनुसार तय समय में पूरा भुगतान नहीं किया गया है जिसके चलते इकरारनामे की शर्तों के अनुसार निष्पादित इकरारनामा निरस्त माना जाए। यह प्रकरण भी वर्तमान में संबंधित न्यायालय में लंबित है।

**मौके पर यथास्थिति के आदेश!! लेकिन इसके बावजूद स्टेशुदा जमीन पर एक पार्टी विशेष के कब्जे पर मोहर लगाते हुए, आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत कर दी गई शराब की दुकान!!**

इस पूरे प्रकरण में दो सालों से दोनों मामले दो न्यायालयों में लंबित है और यथास्थिति के आदेश चलते आ रहे हैं, लेकिन आबकारी विभाग द्वारा एक पार्टी विशेष के कब्जे पर मोहर लगाते हुए, दुकान की लोकेशन स्वीकृत कर दी गई। यदि

यह माना जाए कि संबंधित लाईसेंसी द्वारा ईमानदार आबकारी अधिकारियों को अंधेरे में रख यह सारा कांड करवा दिया गया हो तो यह बात सिर से गले नहीं उतरती क्योंकि परिवादी संतोष कुमार सैनी द्वारा समय रहते ईमानदार और जिम्मेदार आबकारी अधिकारियों को इस पूरे मामले से अवगत करवा दिया गया था। इतना ही नहीं जिम्मेदार आबकारी अधिकारियों के वाट्सअप नंबरों पर भी प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण तथ्य मौजूद है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों की नियत और ईमानदारी पर सवालिया निशान खड़े होना स्वाभाविक है। इसी के साथ यह भी तय है कि आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर राज चरम सीमा पर है। चाहे कोर्ट का आदेश हो या फिर मुख्यमंत्री, वित्त विभाग, आयुक्तालय से आया कोई आदेश, परिवाद या फिर कोई चिट्ठी, इन सभी का जवाब/जांच नीचे पायदान पर बैठा आबकारी निरीक्षक ही देता है या फिर उसे गोलमोल कर देता है।

Number of Case: T.T. 91 ..... 2024 Year: 21

..... 24/8/21 ..... Versus ..... 24/8/21

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of Compliance of the Order
24/8/21	वकील ..... उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण, सांख्यिकी प्रयोजनार्थ दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण सुनवाई एवं विधि अनुसार निस्ताराणार्थ न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम 03 जयपुर महानगर द्वितीय में अंतरित किया जाता है। पक्षकारान/ अधिवक्तागण अंतरित न्यायालय में दिनांक 26/8/21 को उपस्थित हो। पत्रावली इस न्यायालय में फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
23-8-21	पत्रावली 23-8-21	
27-8-21	(राजेश कुमार दड़िया) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम संख्या-03, जयपुर महानगर-II	
20-9-21		

मुख्य प्रतिलिपि प्रतिलिपि त्रयका (जजेश, एस.एस.एस. विधि विभाग लखनौ की पत्रावली) जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय

सुनिश्चित करवाया जा रहा है कि आबकारी अधिकारियों को इस मामले से अवगत करवा दिया गया था।

## एक शराब ठेकेदार विशेष पर जिला आबकारी विभाग की विशेष कृपा के चलते,खेला गया यह खेल!!

आपको बता दें कि एक शराब ठेकेदार विशेष पर जिले के आबकारी अधिकारियों की नजरे इनायत है,जिसके चलते ही स्टेशुदा जमीन पर,कोर्ट के आदेशों की अवमानना बावजूद शराब की दुकान स्वीकृत करने का यह पूरा खेल खेला गया है।इस शराब ठेकेदार को उपकृत करने का यह किस्सा कोई नया नहीं है।इससे पहले भी इस ठेकेदार विशेष को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए,जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया जा रहा है।

इस शराब ठेकेदार विशेष के परिजन के नाम इसी आबकारी वृत पूर्व मे दो साल पहले दुकान संचालित की जा रही थी,जिसके बकाया 52 लाख रुपये बाकी थे।इस शराब ठेकेदार विशेष पर कृपा के चलते,इतनी बड़ी रकम की इन दो सालों मे आबकारी विभाग वसूली नहीं कर पाया है,सूत्रों के अनुसार महज 2-5 लाख रुपये देकर,मामले को ठंडे बस्ते मे डाल दिया गया है।इसी शराब ठेकेदार विशेष के एक अन्य नजदीकी रिश्तेदार के नाम देवस्थान विभाग मे पंजीकृत एक एतिहासिक मंदिर के 200 मीटर के दायरे मे एक दुकान संचालित कर रखी है,जिसे तमाम विरोधों और शिकायतों के बावजूद नहीं हटाया जा रहा है।सूत्रों का कहना है कि जिले के एक मंजले और छोटे साहब की विशेष कृपा के चलते ही इस शराब ठेकेदार विशेष का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।मंजले साहब को तो इस शराब ठेकेदार विशेष को बचाने के लिए एक जांच एजेंसी मे इस शराब ठेकेदार विशेष की पैरवी करते हुए भी कुछ तमाशबीनों द्वारा देखा गया है।हालांकि इन साहब का जयपुर से मोह भंग हो चुका है और दूर दराज के जिले मे अपनी पोस्टिंग करवाने की जुगाड़ मे मंदिर-देवरे धोक लगाते हुए नजर आ रहे है।

### कोर्ट के आदेशों की अवमानना का दोषी कौन?

इस पूरे मामले मे यह तो तय है कि संबंधित आबकारी अधिकारियों द्वारा जानते-बुझते जिंदा मक्खी निगली गई है और शराब ठेकेदार विशेष को लाभ पहुंचाने की नियत से माननीय न्यायालय के आदेशों

की अवमानना की गई है।इस मामले मे परिवादी द्वारा भी आबकारी विभाग को कानून के कटघरे मे खड़ा करने की तैयारी की जा रही है।पूर्व मे भी जयपुर की एक आबकारी निरीक्षक को स्टेशुदा जमीन पर दुकान लगाने की अनुशंसा के चलते बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है,देखना यह है कि कोर्ट,सरकार और विभाग के आला अधिकारियों के संज्ञान मे आने के बाद इस प्रकरण मे किन किन दोषी अधिकारियों पर गाज गिरती है।

